निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार एवं विकास हेतु भिलाई में स्थापित किया गया है।	651	भिलाई नगर निगम को मंगल भवन, के मासिक किराये का भुगतान किया जाता है।	नगर निगम भिलाई को मंगल भवन के मासिक किराये का भुगतान किया जाता है।	651	
2.	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	230000	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर 1450 कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। 150 स्थलों पर मौजूदा CGSWAN का संचालन और रखरखाव, मौजूदा उपकरणों का वार्षिक रखरखाव, 3247 वीडियो कान्फ्रेंसिंग सत्र संचालित किया गया।	153632	
3.	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यो में ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	15300	1. कोर्ट केस प्रबंधन का डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन	डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्रालय स्थापना के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए शत प्रतिशत अचल संपत्ति विवरण प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सचिवालय के माध्यम से संभव हो पाई है। इसके माध्यम से वर्ष 2020-21 में 1124 कर्मचारियों/ अधिकारियों ने ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण का संपादन किया।		
				2. मैन्युअल फाईल ट्रेकिंग सिस्टम (क्यू.आर. कोड़ के साथ) का विकास एवं क्रियान्वयन	डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्रालय स्थापना के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए शत प्रतिशत वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सचिवालय के माध्यम से संभव हो पाई है। इसके		

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					माध्यम से वर्ष 2020-21 में 880 वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन का ट्रांसेक्शन किया।		
				3. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (के.एम.एस.) का क्रियान्वयन	डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्रालय स्थापना के सभी कर्मचारीयों/अधिकारीयों के लिए शत प्रतिशत अवकाश प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल सचिवालय के माध्यम से संभव हो पाई है। इसके माध्यम से वर्ष 2020-21 में 3279 अवकाशों का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया।		
				4. नए सिस्टम इंटीग्रेशन का निविदा के द्वारा चयन 5. परियोजना के वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ निकास प्रबंधन (एक्जिट मैनेजमेंट) का कार्य	डिजिटल सचिवालय परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17-01-2020 में संपन्न हुई। उक्त बैठकों में डिजिटल सचिवालय परियोजना को वर्ष 2020-21 में 12 माह के विस्तार (1 Feb 2020– 31 Jan 2021) प्रदान किया गया। कोविड महामारी एवं लाकडाउन की वजह से PS&IC के समक्ष रखा जाना संभव नहीं हो पाया। चिप्स के कोविड 19 Empower committee दिनांक 19.03.2021 एवं 5.12.2020		

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					में संपन्न हुई। उक्त बैठक में डिजिटल सचिवालय परियोजना की जुन 2021 तक वर्तमान SI को विस्तार प्रदान किया गया।		
4.	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	ग्रामों में नागरिकों को ई-गवर्नेंस एवं ई-भुगतान की सेवाएँ प्रदान करना	1	सामान्य सेवा केन्द्रों का संचालन करना	सामान्य सेवा केन्द्र 2.0 परियोजना अंतर्गत राज्य के 10971 ग्राम पंचायतों में से 10200 ग्राम पंचायतों को परियोजना में सम्मिलित किया जाकर ग्रामीण नागरिको को जनोपयोगी सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।	0	
5.	ई-जिला परियोजना	शासन की प्रमुख जी.2सी. सेवाएँ, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर एवं अधोसंरचना का विकास	65000	प्रचालन एवं रखरखाव, लाइसेंस का ए. एम.सी., एस.एम.एस. सेवा, मानव संसाधन, नई सेवओं और अन्य विविध आवश्यकताओं के लिए	विभागों को जी.2सी. नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना वर्ष 2020-21 में 27.50 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया है। सात नयी सेवाओं को पोर्टल से जोड़ा गया है।	65000	
6.	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिजनेस इनक्यूबेटर की स्थापना तथा प्रचालन किया जा रहा है।	22470	1. 100 से अधिक स्टार्टअपस को इन्क्युबेट किया गया है। 2. स्टार्टअप द्वारा 700 से अधिक रोजगार प्रदान किया जाना 3. राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स में 36 आई.एन.सी. के साथ 2 अन्य स्टार्टअप प्रकाशित हुए।	100 से अधिक स्टार्टअप्स को इन्क्युबेट किया गया है स्टार्टअप द्वारा 700 से अधिक रोजगार प्रदान किया जाना राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स में 36 आई.एन.सी. के साथ 2 अन्य स्टार्टअप प्रकाशित हुए।	8988	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. कई स्टार्टअप्स ने अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पुरस्कार जीता है।	कई स्टार्टअप्स ने अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पुरस्कार जीता है।		
				5. टेक्मेंट नामक स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स को अमेरिका स्थित एक कंपनी ने एक्वायर किया है।	टेक्मेंट नामक स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स को अमेरिका स्थित एक कंपनी ने एक्वायर किया है।		
				6. 36 आई.एन.सी. में स्थित स्टार्टअप फिनोलोजी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम फाइनेंशियल सलाहकार संस्था है।	36 पदब में स्थित स्टार्टअप फिनोलॉजी वेंचर आाईवेट लिमिटेड सेबी द्वारा मान्यता आाप्त आथम फाइनेंशियल सलाहकार संस्था है।		
7.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान	नेशनल ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण - शासकीय सेवकों को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में संबंधित प्रशिक्षण देना	5000	राज्य लोक सेवा आयोग में चयनित नवनियुक्ति डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखाधिकारी आदि को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में संबंधित प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में प्रदान करना।	कोविड-19 स्थिति के कारणवश अकादमी में आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित है।	0	
8.	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य के प्रमुख अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा	7500	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं मॉनिटरिंग टीम की स्थापना	1. बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के मूल्यांकन और समीक्षा में शासन की सहायता के लिये केन्द्रीयकृत परियोजना प्रबन्धन प्रणाली (CPMS) का निर्माण किया गया है, जिससे विभागों द्वारा उनके विभाग में संचालित परियोजना की समय-समय अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					की सतत् निगरानी रखने में आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। 2. इस प्रणाली के अंतर्गत विभागों की परियोजनाओं से संबंधित प्रत्येक स्तर पर डैशबोर्ड एवं एमआईएस का प्रावधान है। 3. मेजरमेंट बुक के वेब एप्लीकेशन एवं मोबाईल-एप का निर्माण भी किया गया जा चुका है। 4. वर्तमान में छत्तीसगढ रोड डेव्हलमेंट कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा मनोनित परियोजनाओं का CPMS ऑटोमेशन का कार्य किया जा चुका है। 5. विभागों में संचालित वित्तीय प्रणाली का CPMS के साथ एकीकरण का कार्य लगभग किया जा चुका है।		
9.	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना	ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों मे निविदा बनाना	15000	विभिन्न विभागों तथा उनकी एजेंसियों को निविदा कार्य हेतु ऑनलाईन सुविधा	वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑनबोर्डेड विभाग/निगम/कार्पोरेशन - 25 वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंजीकृत निविदाकार-3268 वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गई निविदाओं की संख्या-10,188	15000	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गई निविदाओं की कुल लागत- 69,034.79 करोड़		
10.	नागरिक संबंध केन्द्र योजना	शासन की जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन की हितग्राहियों की प्रतिक्रिया के आधार पर समीक्षा	10000	एक कॉल सेंटर की स्थापना एवं समस्त हितग्राहियों के समेकित डेटाबेस का विकास कर शासन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का 'फीडबैक' लेना	वर्तमान में परियोजना का संचालन नही हो रहा है।	0	
11.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	110000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं रोजगार करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक आमुख कुंजी के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्ता को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ ने राज्य की इलेक्ट्रानिक्स सूचना औद्योगिकी एवं सूचना औद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 जारी कर अधिसूचना क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015 एवं क्रमांक 44 दिनांक 5 फरवरी 2016 द्वारा अधिसूचित किया है। चिप्स के इन निवेश संबर्धन आयासों के परिणामस्वरूप राज्य में इलेक्ट्रानिक्स, सूचना औद्योगिकी समर्थित सेवाओं के क्षेत्र में अब तक कुल रू. 607 करोड़ निवेश राशि के 37 आस्तावो को स्वीकृत आदान की गयी ह। जिससे 15,171 लोगो को रोजगार आाप्त होगा।	15000	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेंस कार्यो के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	17422	27 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन करना	1. 27 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन करना 2. जिला स्तर पर परियोजना क्रिन्यावन की मॉनिटरिंग एवं G2C सेवाओं की विभिन्न सेवा श्रेणियों में ट्रांजेक्शन की संख्या की रिपोर्ट। 3. सेवाओं की प्रदायगी की गुणवत्ता के स्तर की मॉनिटरिंग। 4. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तकनी़प46की सहायता हेतु हेल्प डेस्क के साथ समन्वय। 5. जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु समन्वय। 6. तकनीकी अधोसंरचना के आवश्यक रखरखाव एवं कनेक्टिविटी की समीक्षा एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना ।	17422	
13.	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सर्वाजनिक स्थलों पर नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	5200	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में 19 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किया गया। संचालन एवं संधारण किया गया है।	5200	
14.	विशिष्ट पहचान (आधार) परियोजना	राज्य में आधार योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन करना	7000	राज्य के आधार इनरोलमेंट एजेंसी के रूप में चिप्स को तथा पंजीयक के रूप में इ.सू.प्रौ. विभाग को कार्य करने हेतु सक्षम करना	विशिष्ट पहचान परियोजना अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान आाधिकरण (UIDAI) एवं चिप्स का अनुबंध निष्पादित किया गया है जिसके अनुरूप राज्य की विभिन्न हितग्राही मुलक	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					परियोजनाओं में AUA सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।		
15.	भारत नेट परियोजना	राज्य में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क का विस्तार करना	150010	ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना	स्टेट नेटवर्क आपरेंशन सेंटर (SNOC) से एकीकृत ग्राम पंचायत : 3831 आप्टिल फाइबर (OFC) स्थापित : 17915 किलोमीटर ट्रेंचिग और डक्टिंग (T&D) : 20211 किलोमीटर	0	
16.	छत्तीसगढ़ स्टेट स्पासियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सूचनाओं को सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय विभागों हेतु केन्द्रीकृत करना।	26394	विभागों को जीआईएस प्लेटफार्म पर ऑनलाईन प्रदान करना	विस्तृत परियोजना पत्रक (डी.पी.आर) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय सहमति हेतु लंबित है।	0	
17.	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	313800	विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हुत स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	वर्तमान में डेटा सेंटर में 49 रैक्स उपलब्ध हैं, जिसमें 38 विभागों के सर्वर स्थापित किए गए हैं एवं 190 एप्लीकेशन एवं वेबसाइटें होस्ट किये जा रहे हैं।	0	
18.	संचार क्रांति योजना	राज्य में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार एवं मोबाईल के उपयोग को बढ़ावा देना	1000000	मोबाइल वितरण और सेवाओं के लिए कॉन्ट्रेक्टर का लंबित भुगतान	अंतर्गत 2020-21 में मोबाइल वितरण एवं नेटवर्क विस्तार नहीं किया गया है अत: भौतिक प्रगति निरंक है।	700000	
19.	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन योजना अंतर्गत एकीकृत सक्रिय ई-शासन प्रणाली	200000	1. नीति नियोजन उपकरण का डिप्लॉइमेन्ट	1. वर्ल्ड बैंक का पहला माइलस्टोन पूरा किया- राज्य में डेटा एक्सचेंज दिशानिर्देश आकाशित	14078	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
		परियोजना (आई.पी.ई.जी.-7919) की विविध आवश्यकताओं के लिए		2. डाटा शेयरिंग एवं सहमति फ्रेमवर्क नीति और दिशानिर्देशों की अधिसूचना हेतु 3. डायनेमिक लाभार्थी रजिस्ट्री एवं डेटा एक्सचेंज प्लेटफार्म के रोलआउट हेतु 4. ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का आई.पेग में माइग्रेशन हेतु	किया गया है एवं श्रम विभाग में नीति नियोजन उपकरण (पॉलिसी प्लानिंग टूल) लागू किया गया है। 2. वर्ल्ड बैंक का दूसरा माइलस्टोन आंशिक रुप से हासिल किया-डायनामिक बेनेफिशरी रजिस्ट्री और डेटा एक्सचेंज प्लेटफार्म के रोल-आउट के लिए वर्ल्ड बैंक का दूसरी माइलस्टोन का कार्य आगति में है।	
20.	स्टेट पोर्टल परियोजना	परियोजनांतर्गत विकसित नवीन स्टेट पोर्टल हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता होगी जिस हेतु हार्डवेयर आईटम एवं सॉफ्टवेयर लाईसेंस स्टेट डाटा सेन्टर द्वारा प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।	2848	परियोजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है:- 1. राज्य के नवीन पोर्टल एवं पोर्टल की थीम पर विकसित वेबसाईट का रखरखाव सुनिश्चित करना। 2. पोर्टल एवं अन्य वेबसाईट पर नियमित रूप से जानकारी अद्यतन किया जाना एवं अपलोड करना 3. पोर्टल एवं अन्य वेबसाईट के सर्वर का वार्षिक रखरखाव करना। 4. विभिन्न विभागों शासकीय सेवकों एवं नागरिकों को वेबसाईट के माध्यम से उपयोगी जानकारी, टेण्डर, अधिसूचना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करना।	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। अनुमोदन लंबित है।	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	स्थापना मद अंतर्गत कार्यालयीन व्यय आदि का रखरखाव एवं संधारण	115000	चिप्स हेतु स्थायी कार्यालय की स्थापना, जो स्मार्ट सिटी के आई.टी की आवश्यकता में महत्वपूर्ण है।	छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) छ.ग. राज्य में आई.टी. विकास एवं ई-गवर्नेस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। प्रतिनियुक्ति में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान, कार्यालयीन व्यय आदि का रखरखाव एवं संधारण किया जाता है।	15000	
22.	मुख्यमंत्री ई-समीक्षा	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	40000	डैशबोर्ड का निर्माण, जिसमें शासकीय विभागों के मुख्य निष्पादन संकेतक के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकता एवं प्रगति की निगरानी	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागें में प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।	0	
23.	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	एस.टी.पी.आई. के साथ एन.आई.टी रायपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	20000	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप एवं स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम में योगदान	विस्तृत परियोजना पत्रक (डी.पी.आर) STPI भिलाई एवं चिप्स के मध्य तकनीकी एवं MOU संबंधी चर्चा हेतु लंबित है।		
24.	बिल्डनेक्स्ट परियोजना	शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों का वेबसाईट का डिजाईन, संचालन एवं एप्लीकेशन निर्माण करना तथा इसके लिये इन-हाऊस मैनपावर की भर्ती किया जाना	30000	छत्तीसगढ़ शासन के सभी शासकीय विभागों के वेबसाईटों एवं मोबाईल एप्लीकेशन की लागत को 30-40 प्रतिशत कम कर एवं कार्य के गुणवत्ता को बढ़ा देना	परियोजना अंतर्गत कुल 16 मोबाईल एप्लीकेशन एवं 07 वेबसाईट का निर्माण किया गया है। साथ ही 02 वेबसाईट हेतु Elets पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है।	12000	